# अब हर उद्यमी मित्र और जिला महाप्रबंधक को 180 औद्योगिक इकाइयों की मिली जिम्मेदारी

## 75 जिलों के उद्यमी मित्रों और जीएम-डीआईसी की समीक्षा और मूल्यांकन

## जमीन व एनओसी संबंधित समस्याओं के समाधान में करेंगे सहयोग

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने व निवेशकों को जमीनी स्तर पर सहयोग देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने उद्यमी मित्रों और जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों में से प्रत्येक की जवाबदेही तय की गई है। इसके अंतर्गत 180 औद्योगिक इकाइयों को जमीन व एनओसी संबंधित समस्याओं के समाधान, बीमार इकाइयों के पुनरुद्धार और तिमाही मूल्यांकन में सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है।

शुक्रवार को उद्यमी मित्रों और महाप्रबंधकों की 46 दिवसीय राज्यव्यापी समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समीक्षा अभियान दो जून को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसके तहत इन्वेस्ट यूपी ने सभी 75 जिलों में गहन समीक्षा की।

लखनऊ स्थित मुख्यालय में आयोजित सत्रों में जिला उद्योग महाप्रबंधक और उद्यमी मित्रों सहित 155 अधिकारी शामिल हुए। प्रत्येक जिले की टीम ने जमीन की उपलब्धता, परियोजना स्थिति, निवेशक संवाद और भविष्य की कार्ययोजना से संबंधित रिपोर्ट पेश की।

इस दौरान निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त प्रश्नों के समाधान, विभागीय समन्वय और 100 करोड़ से कम निवेश वाले 200 से अधिक लीड्स की प्रगति की भी निगरानी की गई।

इससे पहले 26 से 30 मई के बीच इन्वेस्ट यूपी की टीमों ने 14 जिलों का दौरा कर औद्योगिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया और हस्तक्षेप योग्य क्षेत्रों की पहचान की थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह रणनीतिक समीक्षा अधिकारियों के कामकाज को बेहतर करेगी। अवरोधों दूर होंगे और जिला स्तर पर औद्योगिक रणनीति सशक्त बनेगी। ब्यूरो